केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

जलांश

खंड 5 अंक 01 अगस्त 2022

विषयसूची

- ड्रिप-II और ड्रिप-III की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एनएलएससी) की पहली बैठक
- केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की दूसरी बैठक
- के.ज.आ.का स्टाल और हिसार, हरियाणा में 'आकांक्षी
- (एस्पायरिंग) हरियाणा, 2022' प्रदर्शनी में प्रतिभागी
- पोलावरम सिंचाई (राष्ट्रीय) परियोजना के संबंध में बैठक।
- राष्ट्रीय परियोजनाओं (रेणुकाजी और लखवार परियोजना) के संबंध में बैठक
- वाराणसी में स्वच्छ नदी के लिए एक स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना के संबंध में सचिव(डब्ल्यूआर) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित
- मैसर्स स्टकी द्वारा के.ज.आ. को प्रस्तुत बैराज विकल्प की डीपीआर पर के.ज.आ. की प्रस्तुति
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एन डी एस ए) की वर्चुअल बैठक
- सात नदी घाटियों में अवसादन दर और अवसादन परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधार पर गणितीय मॉडलिंग के लिए कार्यशाला का उद्घाटन
- फरक्का प्रभाव अध्ययन पर समिति की छठी बैठक
- जल संसाधन विभाग-09 की 20वीं बैठक
- डीआरआईपी चरण II के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला कार्यान्वयन समर्थन मिशन
- के.ज.आ. ने पोलावरम परियोजना का दौरा किया
- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में ड्रिप-II के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संबंध में अध्यक्ष (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) के साथ बैठक
- सुबर्णरेखा-महानदी लिंक परियोजना स्थल का दौरा
- ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना (यूएसएमएसपी)
- आईएस कोड से संबंधित टिप्पणियाँ
- देश में बाढ़ की स्थिति - जुलाई 2022
- 31.07.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- जलाशय निगरानी
- जुलाई-2022 के दौरान एन डब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि
- डेटा कॉर्नर- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत लागत और व्यय:
- जल क्षेत्र-समाचार
- गैलरी/आजादी का अमृत महोत्सव
- इतिहास- फरक्का बैराज परियोजना –स्वप्न साकार

डॉ.आर.के. गुप्ता
अध्यक्ष

संदेश

केन–बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, केन–बेतवा लिंक परियोजना (एससी–केबीएलपी) की संचालन समिति की दूसरी बैठक सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जलशक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 20.07.2022 को आयोजित की गई थी।मैंने सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान, विभिन्न एजेंड़ा मदों पर विचार–विमर्श किया गया जिसमें पहली बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई भी सम्मिल्लित थी जैसे वर्ष 2022–23 के लिए कार्य योजना, परियोजना प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति, भूमि अधिग्रहण और प्रभावित गांवों का पुनर्वास, केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के कार्यालयों की स्थापना, बृहत्तर पन्ना के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन, केबीएलपीए की वित्तीय शक्तियां, किए गए व्यय पर राज्य को प्रतिपूर्ति आदि।

केंद्रीय जल आयोग ने डीडब्ल्यूआरआईएस योजना के तहत वर्ष 2009 में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान हिमनदी झीलों (जीएल)/जल निकायों (डब्ल्यूबी) की निगरानी का काम शुरू किया। सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने हिमनद/हिमनद झीलों से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए 11.07.2022 को हिमनद झील भटने से बाढ़ प्रकोप (जीएलओएफ) / भूस्खलनझील भटने से बाढ़प्रकोप(एलएलओएफ) सहित हिमनद झील भटने से बाढ़ प्रकोप के प्रबंधन पर एनडीएमए के दिशानिर्देशों के मद्देनजर एक बैठक कीअध्यक्षता की। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ के.ज.आ, विभिन्न मंत्रालयों और वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

मैंने जल संसाधन परियोजना के क्षेत्र में भारत–नेपाल सहयोग से संबंधित मुद्दों के संबंध में 21.07.2022 को नई दिल्ली में सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, विदेश सचिव और ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लिया। बैठक का प्राथमिक उद्देश्य नेपाल में सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना (एसकेएचडीएमपी) पर अरुण नदी पर प्रस्तावित निम्न अरुण जल विद्युत परियोजना के डीपीआर में अपनाए गए डिजाइन मापदंडों के निहितार्थ पर चर्चा करना था, जिसके लिए भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र सर्वेक्षण और जांच तथा अन्य अध्ययन चल रहे हैं।

इसमें सुधार के लिए समाचार पत्र के सभी पाठकों के सुझावों का स्वागत है।

राकेश गुप्ता

ड्रिप-II और ड्रिप-III की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एनएलएससी) की पहली बैठक

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) चरण-II के लिए राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एनएलएससी) की पहली बैठक 04.07.2022 को सचिव जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। श्री जे. चंद्रशेखर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ ने बैठक में भाग लिया जिसमें एजेंडा बिंदुओं जैसे बाहरी वित्त पोषण की स्थिति और इसकी प्रभावशीलता, वर्तमान भागीदार राज्यों और अतिरिक्त राज्यों को शामिल करने, भौतिक और वित्तीय प्रगति, डीईए की परियोजना तैयारी मानदंड, उत्कृष्टता केंद्र की स्थिति, एससीडीएस और एसडीएसओ की अधिसूचना, ड्रिप चरण-II के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) के गठन और सीपीएमयू सलाहकार की भर्ती पर चर्चा की गई। बैठक में समिति के सदस्यों, मंत्रालय, के.ज.आ, विश्व बैंक और कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों ने भाग लिया।

केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की दूसरी बैठक

केन-बेतवा लिंक परियोजना (एससी-बीएलपी) की संचालन समिति की दूसरी बैठक 20.07.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों और के.ज.आ, नीति आयोग तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में जोर देकर कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के जल सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, को समयबद्ध तरीके से अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लागू किया जाना चाहिए और परियोजना से प्रभावित लोगों के आर एंड आर की विधिवत देखभाल और क्षेत्र के संरक्षण, विशेष रूप से पन्ना टाइगर रिजर्व की परिदृश्य पर निर्भर प्रजातियों की जानकारी रखनी चाहिए।

बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई भी समिल्लित थी जैसे वर्ष 2022-23 के लिए कार्य योजना, परियोजना प्रबंधन परामर्श की नियुक्ति, भूमि अधिग्रहण और प्रभावित गांवों का पुनर्वास, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के कार्यालयों की स्थापना, बृहत्तर पन्ना के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन, केबीएलपीए की वित्तीय शक्तियां, किए गए व्यय पर राज्य को प्रतिपूर्ति आदि।

विभिन्न योजना और तकनीकी मामलों पर प्राधिकरण की समीक्षा करने और सलाह देने के लिए केबीएलपी के लिए एक तकनीकी सलाहकार समूह का गठन करने का भी प्रस्ताव था।

पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आर एंड आर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक आर एंड आर समिति गठित करने का प्रस्ताव था।परियोजना के परिदृश्य प्रबंधन प्लान (एलएमपी) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के कार्यान्वयन के लिए एक ग्रेटर पन्ना परिदृश्य परिषद का गठन भी प्रस्तावित किया गया था।

Source: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1843201

जल संसाधन के क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

डॉ. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ और श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य, डीएंडआर ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत-नेपाल सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 21.07.2022 को आयोजित बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता डीओडब्ल्यूआर आरडी एंड जीआर के सचिव, विदेश सचिव और विद्युत सचिव ने संयुक्त रूप से की थी। बैठक का प्राथमिक उद्देश्य सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना (एसकेएचडीएमपी), नेपाल की अरुण नदी पर प्रस्तावित निम्न अरुण जल विद्युत परियोजना के डीपीआर में अपनाए गए डिजाइन मापदंडों के निहितार्थ पर चर्चा करना था, जिसके लिए भारत और नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र सर्वेक्षण और जांच और अन्य अध्ययन चल रहे हैं।

इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और इस बैठक में लोअर अरुण एचईपी और सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निर्णय लिए गए।

हिमनदों/ग्लेशियल झीलों के फटने (जीएलओएफ)/भूस्खलन झील के फटने के प्रवाह (एलएलओएफ) सहित हिमनदों / ग्लेशियल झीलों से संबंधित प्रबंधन, निगरानी और अध्ययन

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने हिमनद/हिमनद झीलों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 11.07.2022 को हिमनद झील भटने से बाढ़ प्रकोप (जीएलओएफ) / भूस्खलनझील भटने से बाढ़प्रकोप(एलएलओएफ) सहित हिमनद झील भटने से बाढ़ प्रकोप के प्रबंधन पर एनडीएमए के दिशानिर्देशों के मद्देनजर एक बैठक कीअध्यक्षता की। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ के.ज.आ, विभिन्न मंत्रालयों और वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) ने डीडब्ल्यूआरआईएस योजना के तहत वर्ष 2009 में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान हिमनद झीलों (जीएल)/जलनिकायों (डब्ल्यूबी) की निगरानी का काम शुरू किया। उपग्रह इमेजरी डेटा के आधार पर एनआरएससी, हैदराबाद के सहयोग से जून, 2011 में हिमनद झील/जलनिकायों की सूची प्रकाशित की गई थी। इस सूची के अनुसार, भारतीय नदी घाटियों के हिमालयी क्षेत्र में 50 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले 477 हिमनद झील/ जलनिकायों सहित 10 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले 2,028 हिमनद झील/जलनिकायों हैं। वर्तमान में, के.ज.आ हर साल मानसून के मौसम (जून से अक्टूबर) के दौरान मासिक आधार पर 50 हेक्टेयर से बड़े हिमनद झील/जलनिकायों की निगरानी कर रहा है, जिनमें से 95 हिमनद झील/जलनिकायों भारत में हैं।

हिमनदी झील की निगरानी झीलों के आकार में किसी भी अप्रिय वृद्धि का आकलन करने और बाद में हिमनद झील प्रकोप बाढ़

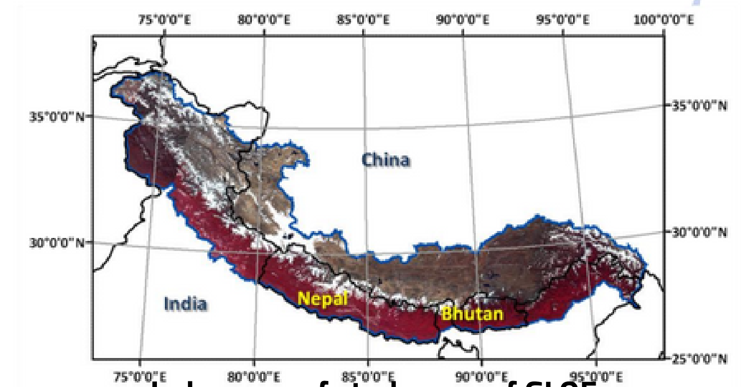

Index map of study area of GLOF

(जीएलओएफ) अध्ययन करने में मदद करती है। निगरानी रिपोर्ट को जल शक्ति मंत्रालय, के.ज.आ के संबंधित क्षेत्र कार्यालयों, संबंधित हिमालयी राज्यों, के.ज.आ के क्षेत्र कार्यालयों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जा रहा है।

हाल ही में, के.ज.आ ने 10 हेक्टेयर से कम आकार के हिमनद की निगरानी शुरू की है और महत्वपूर्ण हिमनद के लिए एक महीने से भी कम समय में अवलोकन की आवृत्ति की जाएगी, जिससे निगरानी के तहत हिमनदों / जलनिकायों की कुल सूची बढ़कर 901 हो गई है। के.ज.आ द्वारा निगरानी किए जा रहे ग्लेशियरों के आकार की स्वचालित व्याख्या के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

के.ज.आ झीलों के स्थान, संबद्ध मदर ग्लेशियरों और झीलों और ग्लेशियरों के आसपास स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर परियोजना जलग्रहण क्षेत्र में संभावित खतरनाक हिमनद झीलों की पहचान करने के लिए परियोजना विशिष्ट जीएलओएफ अध्ययन में भी शामिल है।

मैसर्स स्टकी द्वारा के.ज.आ. को प्रस्तुत बैराज विकल्प की डीपीआर पर के.ज.आ. की प्रस्तुति

श्री जे चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ., श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता और श्री एस.के. दास, निदेशक ने के.ज.आ. (मुख्यालय), नई दिल्ली में 02.07.2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गठित स्वतंत्र समिति के समक्ष मैसर्स स्टकी द्वारा के.ज.आ. को प्रस्तुत बैराज विकल्प की डीपीआर पर के.ज.आ. की प्रस्तुति में भाग लिया।

के.ज.आ. का स्टाल और हिसार, हरियाणा में 'आकांक्षी (एस्पायरिंग) हरियाणा, 2022' प्रदर्शनी में प्रतिभागी

मुख्य अभियंता (वाईबीओ), अधीक्षण अभियंता (योजना मंडल) और पी एंड आई डिवीजन के.ज.आ, फरीदाबाद के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सदस्य (आरएम), के.ज.आ ने हिसार, हरियाणा में 28 से 30 जुलाई, 2022 के दौरान "आकांक्षी हरियाणा -2022" में भाग लिया।

प्रदर्शनी के दौरान, जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में आगंतुकों को जानकारी देने का प्रयास किया गया।जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, पीएमकेएसवाई, नमामि गंगे कार्यक्रम, अटल भूजल योजना, बाढ़ पूर्वानुमान आदि के बारे में जानकारी पोस्टर, फ्लेक्स बैनर, ऑडियो-वीडियो फिल्मों आदि के माध्यम से प्रदर्शित की गई।

यह सूचित किया जाता है कि प्रदर्शनी अवधि के दौरान जल शक्ति

मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के ख़ेमे ने विशेष रूप से हिसार जिले और उसके आसपास के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों की भारी भीड़ को आकर्षित किया। सभी आगंतुकों को स्टॉल के विषय और उसमें मौजूद सामग्री के बारे में विस्तार से बताया गया। यह कार्यक्रम बड़ी सफलता के साथ समाप्त हुआ और जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग विभाग के ख़ेमे ने सर्वश्रेष्ठ स्टाल पुरस्कार जीता।

पोलावरम सिंचाई (राष्ट्रीय) परियोजना के संबंध में बैठक

भारत सरकार ने लोगों के लाभ के लिए पहचान की गई राष्ट्रीय परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की दृष्टि से ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक योजना को मंजूरी दी।राष्ट्रीय परियोजनाओं को केंद्रीय अनुदान के रूप में सिंचाई और पेयजल घटक की लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामय्यापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। इस बहुउद्देशीय प्रमुख परियोजना में 4.36 लाख हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता बढाने के लिए एक मृदा सह प्रस्तरपूर (ईसीआरएफ) बांध के साथदोनों किनारों पर काठी मृदा बांध, एक उत्प्लाव, सिंचाई सुरंग, नौसंचालन सुरंग व चैनल और दो मुख्य नहरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 960 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन, 540 गांवों को पेयजल आपूर्ति और 84.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी (नुकसान सहित) को कृष्णा बेसिन में मोड़ने की भी परिकल्पना की गई है।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग विभाग की अध्यक्षता में एक आंतरिक समीक्षा बैठक 13.07.2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें पोलावरम सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति,गैप-I और II के प्रभावित क्षेत्र में अपनाए जाने वाले उपचार/उपायों की स्थिति जानने और प्रतिपूर्ति हेतु लंबित बिलों/दावों के विवरण पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग (आंध्र प्रदेश सरकार), पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा, इस बैठक के बाद पोलावरम सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए माननीय मंत्री (जलशक्ति) द्वारा 14.07.2022 को एक समीक्षा बैठक की गई।

उक्त बैठक के दौरान, लिए गए मुख्य निर्णय थे- स्पिलवे के माध्यम से गुजरने वाली विभिन्न बाढ़ों के लिए स्पिलवे के अनुप्रवाह / अनुप्रवाह कॉफर बांध के निकट जल स्तर में उतार-चढ़ाव का निर्धारण करने के लिए तुरंत एक अध्ययन कराना, अनुप्रवाह कॉफर बांध के पूर्ण हिस्से में उपरिप्लाव की संभावना का पता लगाना, पोलावरम परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के बिलों की प्रतिपूर्ति में तेजी लाना जिसका प्रयास वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है।

साथ ही, पीपीए को निर्देश दिया गया कि अनुप्रवाह कॉफ़र बांध के एक हिस्से में उपरिप्लाव के कारण परियोजना के निष्पादन में देरी की ओर इशारा करते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार को एक पत्र जारी करें।

सुबर्णरेखा-महानदी लिंक परियोजना स्थल का दौरा

सुबर्णरेखा-महानदी (एस-एम) लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के हिमालयी नदियों के विकास घटक के तहत नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं में से एक है। के.ज.आ (प्लानिंग सर्कल फरीदाबाद, बीसीडी (ई एंड एनई) निदेशालय और हाइड्रोलॉजी (एन) निदेशालय) के अधिकारियों की एक टीम ने एनडब्ल्यूडीए के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से 11.07.2022 से 17.07.2022 के दौरान प्रस्तावित एसएम लिंक परियोजना का दौरा किया। इस संयुक्त दौरे का उद्देश्य डिजाइनरों को परियोजना स्थल की स्थानीयस्थितियों से परिचित कराना और स्थल पर विभिन्न डिजाइन मापदंडों की चर्चा करना था ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर डीपीआर की तैयारी में तेजी लाई जा सके।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में ड्रिप चरण-द्वितीय के कार्यान्वयन में तेजी लाने के संबंध में अध्यक्ष (बीबीएमबी) के साथ बैठक

परियोजना निदेशक, डीआरआईपी चरण- II और चरण- III और श्री समीर कुमार शुक्ला, निदेशक (एफई एंडएसए) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की यात्रा के दौरान अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के साथ थे। यह दौरा डीआरआईपी चरण- II के कार्यान्वयन की स्थिति-समीक्षा और कार्य में तेजी लाने के संबंध में 12.07.2022 को अध्यक्ष (बीबीएमबी) के साथ बैठक करने के लिए किया गया था और क्रमशः 12-13 जुलाई 2022 को भाखड़ा बांध और पोंग बांध का दौरा किया गया।

वाराणसी में स्वच्छ नदी के लिए एक स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना के संबंध में सचिव(डब्ल्यूआर) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

माननीय प्रधान मंत्री ने डेनमार्क की माननीय प्रधान मंत्री एच.ई.एम. मेटे फ्रेडरिकसन की 09.10.2021 को भारत यात्रा के दौरान मुलाकात के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित घोषणा की:

- स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओईएसडब्ल्यूआरएम) की स्थापना
- पणजी में स्मार्ट सिटी लैब की तर्ज पर वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित करें।

उपरोक्त घोषणा के अनुसरण में; साफ और सुरक्षित जल के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से दिसंबर,2021 से जुलाई 2022,के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, के.ज.आ., एनएमसीजी और डेनमार्क के दूतावास के शहरी विकास स्कंध के बीच कई बैठकें हुईं।

इस श्रृंखला में पणजी में स्थापित स्मार्ट सिटी लैब की तर्ज पर वाराणसी में नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए लैब की स्थापना के संबंध में 12.07.2022 को बैठक हुई। श्री जी अशोक कुमार, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी),के.ज.आ., श्री पीएम स्कॉट, सदस्य (आरएम), के.ज.आ., सुश्री अनीता कुमारी शर्मा, काउंसलर, शहरी विकास, डेनिश दूतावास और अन्य संबंधित अधिकारियों ने बैठक में

भाग लिया। बैठक के दौरान, वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने के तौर-तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। वाराणसी में स्वच्छ नदी के लिए एक स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने के संबंध में 29.07.2022 को के.ज.आ., एनएमसीजी और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक और बैठक हुई।इस बैठक में, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग विभाग ने निर्णय लिया था कि अधिकारियों की एक टीम को प्रोजेक्ट अर्बन लिविंग लैब, पणजी, गोवा पर काम करने वाली टीम/अधिकारियों से मिलने और चर्चा करने के लिए गोवा का दौरा करना चाहिए।

वर्चुअल राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एन डी एस ए) की बैठक

एनडीएसए की स्थापना, लेखा प्रमुख बनाना और एनडीएसए के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशालाओं के आयोजन हेतु सड़क मानचित्र निर्माण पर चर्चा करने के लिए श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, अध्यक्ष, एनडीएसए और सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में 11.07.2022 को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी जिससे डीएसए, 2021 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों को संवेदनशील बनाया जा सके।

सात नदी घाटियों में अवसादन दर और अवसादन परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधार पर गणितीय मॉडलिंग के लिए कार्यशाला का उद्घाटन

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के तहत सात नदी घाटियों में तलछट दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग परियोजना के तहत के.ज.आ, मुख्यालय, नई दिल्ली में 14-15 जुलाई 2022 के दौरान "अपनाए गए दृष्टिकोणों और विधियों का अवलोकन, रामगंगा, बराक और नर्मदा घाटियों पर रूपात्मक विश्लेषण और अवसादन मॉडलिंग का अवलोकन" पर तीसरी कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन श्री जे चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ द्वारा किया गया था। कार्यशाला के दौरान तलछट निर्माण घटना,

तलछट परिवहन तंत्र, नदियों की रूपात्मक विशेषताओं और रामगंगा, बराक और नर्मदा घाटियों पर तलछट जमाव जैसे विषयों को शामिल किया गया।

पुनातसांग्चू-II प्राधिकरण की 16वीं बैठक

श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर) के साथ श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, श्री एस.के.दास, निदेशक और श्री अमित रंजन, निदेशक ने 19.07.2022 को पुनातसांगचू-II जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण (पीएचपीए-II) की 16वीं बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान परियोजना के निर्माण और समापन कार्यक्रम के साथ-साथ अन्य तकनीकी मामलों की भी समीक्षा की गई।

जल संसाधन विभाग-09 की 20वीं बैठक

जल संसाधन विभाग-09 (बांध और जल निकासी अनुभागीय समिति), भारतीय मानक ब्यूरो की 20वीं बैठक 01.07.2022 को आभासी मोड में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, डिजाइन (ई एंड एनई) ने की। निदेशक (सी एमडीडी, ई एंड एनई), निदेशक (सीएमडीडी, एन एंड डब्ल्यू) और निदेशक (सीएमडीडी, एनडब्ल्यू एंड एस) ने भी बैठक में भाग लिया।

फरक्का प्रभाव अध्ययन पर समिति की छठी बैठक

श्री जे. चंद्रशेखर, सदस्य (डी एंड आर) ने "बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे का अध्ययन" करने के लिए समिति की 6वीं बैठक में भाग लिया, जो परियोजना की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 29.07.2022 को डॉ. आर.के. गुप्ता, अध्यक्ष, के.ज.आ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ, जीएफसीसी, बिहार सरकार और एनआईएच पटना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अध्ययन का उद्देश्य था- बाढ़ की अलग-अलग वापसी अवधि के परिदृश्य में नदीपर इसके प्रभाव को स्थापित करने के लिए फरक्का बैराज के पश्चजल का अध्ययन करना, पूरे बिहार राज्य में गंगा नदी और उसकी उपरोक्त सहायक नदियों में बाढ़ और गाद जमाव पर परिचालन नीति के संदर्भ में फरक्का बैराज के प्रभाव की पहचान करनाऔर बाढ़ की विभिन्न वापसी अवधि के संबंध में गाद भार व अवसादन का आकलन करना तथा गंगा नदी में अवसादन के कारण चरम बाढ़ से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करना।

ड्रिप चरण II के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला कार्यान्वयन समर्थन मिशन

विश्व बैंक द्वारा पहला कार्यान्वयन समर्थन मिशन दो चरणों में आयोजित किया गया था। मिशन का पहला चरण 11-13 जुलाई 2022 के दौरान मदुरै (तमिलनाडु) में आठ (8) कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के लिए आयोजित किया गया था। मिशन के दूसरे चरण में 15-17 जुलाई 2022 के दौरान देहरादून (उत्तराखंड) में शेष आठ (8) आईए को शामिल किया गया। 26.07.2022 को सात (7) नए ड्रिप राज्यों(बीबीएमबी, डीवीसी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, पंजाब और झारखंड) के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसके बाद 28.07.2022 को नई दिल्ली में सभी आईए के साथ एक समापन बैठक हुई। समीक्षा मिशन के दौरान, विश्व बैंक ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और एसपीएमयू सुदृढ़ीकरण, पर्यावरण और

सामाजिक पहलुओं, विशेषज्ञों की भर्ती (सीएस एंड क्यूए, ईएंडएस, खरीद आदि), अनुबंधों और परियोजना कार्यान्वयन में विभिन्न बाधाओं पर जोर देने के साथ आईए-वार निष्कर्ष प्रस्तुत किए। बैठकों में मुख्य अभियंता, डीएसओ के साथ निदेशक, डीएसआर निदेशालय और के.ज.आ, में ड्रिप के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

के.ज.आ. ने पोलावरम परियोजना का दौरा किया

के.ज.आ, की डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस) इकाई के अधिकारियों ने चल रही पोलावरम परियोजना का 31.07.2022 को दौरा किया क्योंकि परियोजना पर जुलाई 2022 के दौरान उच्च बाढ़ निर्वहन देखा गया।

के.ज.आ, टीम में श्री कयूम मोहम्मद, निदेशक, सीएमडीडी (एनडब्ल्यू एंड एस), श्री दीपक चंद्र भट्ट, निदेशक, तटबंध (एनडब्ल्यू एंड एस) और श्री गौरव तिवारी, सहायक निदेशक, तटबंध (एनडब्ल्यू एंड एस), के.ज.आ, शामिल थे। जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारी के.ज.आ, टीम के साथ थे। संयुक्त टीम ने उत्प्लाव, निर्देश बंध, गैप-I और गैप-II के प्रस्तावित तटबंध बांध के हिस्से, प्रतिप्रवाह कॉफर बांध, अनुप्रवाह कॉफर बांध का दौरा किया और भारी बाढ़ के

मद्देनजर किए गए कार्यों और कार्यों की सामान्य प्रगति की भी समीक्षा की। संयुक्त टीम ने के.ज.आ, पोलावरम जीएंडडी साइट का भी दौरा किया।

एनडब्ल्यूआईसी/वाप्कोस द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति पर एकीकृत जल और फसल सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईडब्ल्यूसीआईएमएस) के संबंध में समीक्षा बैठक

श्री जे चंद्रशेखर अय्यर, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में एकीकृत जल और फसल सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईडब्ल्यूसीआईएमएस) के परियोजना विवरण दस्तावेजों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 06.07.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ ने एकीकृत जल और फसल सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईडब्ल्यूसीआईएमएस) के संबंध में एनडब्ल्यूआईसी, वैपकोस, धर्म पोर्टल आदि को एकीकृत करने के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया।

"जल निकायों की योजनाओं के एसएमआई और आरआरआर के संबंध में डीपीआर तैयार करने के लिए दिशानिर्देश बनाने" हेतु समिति की पहली बैठक

सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (डब्ल्यूबीएस की आरआरआर) योजनाओं के संबंध में विस्तृतपरियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए दिशानिर्देश बनाने हेतु 05.07.2022 को हाइब्रिड मोड में समिति की पहलीबैठक के.ज.आ, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, डिजाइन (ई एंड एनई) ने इसमें भाग लिया।

राष्ट्रीय परियोजनाओं (रेणुकाजी और लखवार परियोजना) के संबंध में बैठक

राष्ट्रीय परियोजना में से एक, रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरि नदी के पर 498 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) के सजीव भंडारण के साथ 148 मीटर ऊंचे प्रस्तरपूर बांध के निर्माण की परिकल्पना करती है। परिकल्पित लाभ में दिल्ली के एनसीटी को पानी की आपूर्ति करना और 40 मेगावाट (स्थापित क्षमता) प्रासंगिक बिजली उत्पादन करना हैं। परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) द्वारा क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, एक राष्ट्रीय परियोजना भी है, जिसमें उत्तराखंड में यमुना नदी पर 330.66 एमसीएम के सजीव भंडारण के साथ 204 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 300 मेगावाट (3X100 मेगावाट) है, जो 33,780 हेक्टेयर को सिंचाई लाभ और 78.83 एमसीएम पेयजल तथा औद्योगिक जल आपूर्ति प्रदान करेगी। इस परियोजना में लखवार बांध के 13.6 किमी नीचे की ओर काटापथेर बैराज के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) और रेणुकाजी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) के निर्माण, लक्षित कार्य की पूर्णता, जल-अनुसूची जारी करना और पानी की मात्रा के संबंध परियोजना की कार्य प्रगति और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 26.07.2022 को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी बांध परियोजना के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि कार्य के निष्पादन और प्रगति में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी मुद्दे स्पष्ट हैं। उन्होंने के.ज.आ. और हिमाचल प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से बैठक कर जल्द से जल्द डिजाइन को अंतिम रूप देने की सलाह दीबैठक में यह भी बताया गया कि टेंडर को अंतिम रूप देने और जल्द से जल्द काम सौंपे जाने की जरूरत है।

इसके अलावा, लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में, केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि कार्य के निष्पादन और प्रगति के संबंध में, कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है अतः के.ज.आ., जल शक्ति मंत्रालय और मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार को परियोजना को प्राथमिकता पर रखने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि काम जल्द से जल्द शुरू हो।

ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना (यूएसएमएसपी)

27.07.2022 को समिति कक्ष, प्रथम तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना(यूएसएमएसपी) की बैठक में श्री विजय सरन, मुख्य अभियंता, डिजाइन (ई एंड एनई) ने भाग लिया।

देश में बाढ़ की स्थिति - जुलाई 2022

ब्रह्मपुत्र, बराक और झेलम घाटियों में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2022 से शुरू हुई। 01 मई से 31 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान, 3520 बाढ़ पूर्वानुमान (2492 स्तर और 1028 अंतर्वाह) जारी किए गए, जिनमें से 3340 (2395 स्तर और 945 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 94.88% सटीकता की सीमा के भीतर थे। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से जुलाई माह में रेड बुलेटिन के 64 (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 124 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2022 से 31.07.2022 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश।

चरम बाढ़ की स्थिति

पाँच बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्र.सं	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1.	असम	नगांव	कोपिली	कामपुर	15/05/2022 16/06/2022	21/05/2022 22/06/2022
2.	बिहार	किशनगंज	महानंदा	तैयबपुर	29/06/2022	29/06/2022
3.	तेलंगाना	भूपालपल्ली	गोदावरी	कालेश्वरम	14/07/2022	15/07/2022
4.		कुमारमभीम	वर्धा	सिरपुर(टी)	14/07/2022	17/07/2022
5.	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीताराम राजू	साबरी	चिंटूरु	15/07/2022	19/07/2022

इक्कीस बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

गंभीर बाढ़ की स्थिति वाले बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र:

असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में 49 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 28 एफएफ स्टेशनों पर बाढ़ की स्थिति सामान्य से ऊपर देखी गई।

सीमा से अधिक प्रवाह वाले जलाशय:

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 52 जलाशयों में उनकी सीमा से अधिक जल प्रवाह हुआ।

आईएस कोड से संबंधित टिप्पणियाँ

आईएस 6934:2014 (उच्च ओगी अधिप्रवाही उत्प्लाव के जलीय डिजाइन) पर प्राप्त टिप्पणियों पर चर्चा की गई/समाधान किया गया और कोड को व्यापक परिसंचरण के लिए भेजा गया। इसके अलावा, आईएस 12804 (उत्प्लावमार्ग और निर्गम संरचना के लिए वातन मांग के अनुमान (हेतु मानदंड), कंक्रीट से बने प्रस्तरपूर बांध के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशानिर्देश, सुरंग और कूपक उत्प्लावमार्ग के लिए जलीय डिजाइन पर विचार, सीढ़ीदार उत्प्लाव के जलीय डिजाइन पर बैठक में चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

31.07.2022 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-2023	व्यय	व्यय(%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	185.000	38.385	20.75%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	8.000	1.6784	20.98%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	23.203	2.7951	12.05%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.15	0.132	1.18%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	44.37	2.1467	4.84%
6	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	100.00	38.385	20.75%

जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 46 जलाशयों में 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ जल विद्युत लाभ है। इन 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.83% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 28.07.2022 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 101.472 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 57 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 85.541 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 72.789 बीसीएम था।

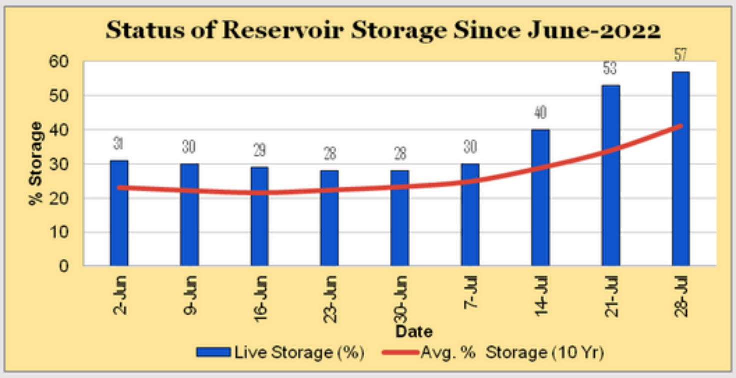

इस प्रकार, दिनांक 28.07.2022 के बुलेटिन के अनुसार 143 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 119 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 139 प्रतिशत है।

जुलाई-2022 के दौरान एन डब्ल्यूए, पुणे द्वारा प्रशिक्षण गतिविधि

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या प्रति पाठ्यक्रम	श्रेणी
1	गूगल अर्थ इंजन का परिचय और जल संसाधन प्रबंधन में इसका अनुप्रयोग (एनएचपी के तहत)	27 जून - 08 जुलाई 2022	27	तकनीकी

अद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च।
तस्मात् सर्वेषु दानेषु तयोदानं विशिष्यते।।

जल से संसार के सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और जीवित रहते हैं. अत: सभी दानों में जल का दान सर्वोत्तम माना जाता है.

डेटा कॉर्नर- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्वीकृत लागत और व्यय:

क्रम सं.	राज्य	नदी	स्वीकृत लागत	जून, 2022 तक राज्य सरकार दवारा किया गया व्यय
1	आंध्र प्रदेश	गोदावरी	110.21	19.59
2	गोवा	मांडोवी	14.10	13.50
3	गुजरात	साबरमती, मिंधोला, तापी	1779.78	1010.51
4	झारखंड	सुवर्णरेखा	3.14	0.98
5	जम्मू और कश्मीर	देविका और तवी	186.74	49.00
6	कर्नाटक	पेन्नार, भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी, तुंगा	66.25	53.59
7	केरल	पम्बा	18.45	33.69
8	मध्य प्रदेश	ताप्ती, वैनगंगा, नर्मदा	20.16	9.67
9	महाराष्ट्र	कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, तापी, मूलामुथा	1182.86	214.91
10	मणिपुर	नम्बुल	97.72	42.22
11	नागालैण्ड	दीफू और धनसिरी	78.65	54.42
12	ओड़िशा	ब्राह्मणी, महानदी, तटीय क्षेत्र	92.74	90.25
13	पंजाब	सतलुज, ब्यास और सतलुज, घग्गर	774.43	797.41
14	सिक्किम	रानीचू, तीस्ता	463.05	225.54
15	तमिलनाडु	कावेरी, अडयार, कूम, वैगई, वेन्नार, ताम्रबरनी	908.13	901.17
16	तेलंगाना	गोदावरी, मूसी	345.72	346.83
	कुल:		6142.12	3863.28

Source: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1845896

जल क्षेत्र समाचार

- असम में बाढ़ के लिए जलवायु परिवर्तन, खराब नीतियां जिम्मेदार (राष्ट्रीय सहारा, 04.07.2022)
- जम्मू-कश्मीर में बाढ़ प्रबंधन के लिए 1,600 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी (राष्ट्रीय सहारा, 09.07.2022)
- बस्तर के नेशनल हाईवे पर चली मोटर बोट, आंध्र से छग का टूटा संपर्क (हरिभूमि, 13.07.2022)
- 'जल संरक्षण को जन आंदोलन बना यूपी को बनाएंगे खुशहाल' (राजस्थान पत्रिका, 18.07.2022)
- बाढ़ प्रबंधन राज्य सूची का विषय: शेखावत (जनसत्ता, 22.07.2022)
- जलवायु परिवर्तन से संवेदनशील हिमालय पर खतरा बढ़ रहा है: विशेषज्ञ (जनसत्ता, 24.07.2022)
- गंगा में अब भी जा रहा 50 प्रतिशत गंदा पानी: एनजीटी (अमर उजाला, 25.07.2022)
- प्रयागराज में बाढ़ का खतरा, बढ़ रहा गंगा-यमुना का जलस्तर (राजस्थान पत्रिका, 26.07.2022)
- गंगा प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, नमामि गंगे परियोजना का मांगा हिसाब, कहा - क्यों न खत्म कर दें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अमर उजाला, 28.07.2022)
- देशभर में मानसून मेहरबान, अब तक 9 फीसदी अधिक पानी बरसा (राजस्थान पत्रिका, 30.07.2022)

गैलरी/आजादी का अमृत महोत्सव

21-22 जुलाई, 2022 को कावेरी बेसिन में अपर कावेरी सब-डिवीजन द्वारा बनाए गए 4 हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन साइट्स और 3 स्टैंड अलोन टेलीमेट्री स्टेशनों का दौरा

श्री एस.के. सिब्बल, मुख्य अभियंता, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) और श्री एन.एस. शेखावत, निदेशक, एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) ने जयपुर, राजस्थान में 09.07.2022 को आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं परिषद बैठक में भाग लिया।

श्री धीरज पांडे, सहायक निदेशक, बीसीडी (ई एंड एनई) ने 04.07.2022 से 06.07.2022 के दौरान "जलशक्ति अभियान-कैच द रेन 2022" (जेएसएसीटीआर) के तहत चल रहे और पूर्ण किए गए कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए धनबाद जिले, झारखंड का दौरा किया।

श्री समीर कुमार शुक्ला (निदेशक, सीडब्ल्यूसी और श्री प्रभात कुमार (उप निदेशक), सीडब्ल्यूसी ने, परियोजना निदेशक, डीआरआईपी चरण- II और चरण- III सहित अतिरिक्त सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के साथ अध्यक्ष (बीबीएमबी) के साथ बैठक के लिए 12.07.2022 को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड(बीबीएमबी) का दौरा किया।

इतिहास- फरक्का बैराज परियोजना – स्वप्न साकार कलकत्ता (अब कोलकाता) बंदरगाह

कलकत्ता (अब कोलकाता) बंदरगाह

भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक शहरों में से एक है। कलकत्ता बंदरगाह समुद्र से लगभग 200 किमी की दूरी पर निचले हुगली पर स्थित है।पोर्ट का भीतरी भाग 200 मिलियन की आबादी के साथ एक मिलियन वर्ग किमी से अधिक में फैला हुआ है।नेपाल और भूटान भी कलकत्ता बंदरगाह का उपयोग करते हैं। 1964-66 में कलकत्ता बंदरगाह द्वारा संचालित यातायात की मात्रा 1800 से अधिक जहाजों और 11 मिलियन टन तक के शिखर पर पहुंच गई थी।तब से यह ट्रैफिक लगातार कम होता जा रहा था। कलकत्ता बंदरगाह के उत्तरोत्तर ह्रास के कारणों की तलाश करना दूर नहीं था।

हुगली नदी

हुगली नदी का निर्माण गंगा के तीन उद्गम भागीरथ, जलांगी और चुन्नी से हुआ है। लगभग तीन शताब्दी पूर्व तक मुख्य गंगा भागीरथ-हुगली प्रणाली से होकर बहती थी।तत्पश्चात नदी ने मुख्य रूप से अपने बाईं छोर, यानी पद्मा के माध्यम से बहने की प्रवृत्ति विकसित की। नतीजतन, भागीरथी एक उत्प्लाव वाहिका की स्थिति में जलावनत हो गई।19वीं शताब्दी में नदी की गिरावट महत्वपूर्ण हो गई और 20वीं शताब्दी में खतरनाक हो गई।1918 से, शुष्क मौसम के दौरान भागीरथी चैनल में प्रवाह बंद हो जाता है, इस प्रकार पिछले 57 वर्षों से हुगली शुष्क मौसम प्रवाह से वंचित है। मानसून के दौरान हुगली में प्रवेश करने वाली मिट्टी और रेत गैर-मानसून अवधि के दौरान ऊपरी भूमि प्रवाह की कमी के कारण समुद्र में नहीं जा रही है। दूसरी ओर, समुद्र से ज्वार-भाटा गाद को ऊपर की ओर धकेलता है और नदी में रेत के जमाव को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप जहाजों के लिए नदी के चैनलों के माध्यम से कलकत्ता बंदरगाह तक पहुँचने के लिए आवश्यक ड्राफ्ट में कमी आती है, जिससे नौवहन संबंधी खतरे पैदा होते हैं। इसके अलावा धीरे-धीरे ऊपर के मीठे पानी के चैनलों के अवरुद्ध होने के परिणामस्वरूप हुगली की लवणता में वृद्धि हुई है जो कलकत्ता और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति करती है।

बैराज की आवश्यकता

अतीत में भागीरथी हुगली प्रणाली में सुधार के कई प्रस्तावों पर विचार किया गया था। यहां तक कि 1958 में ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा राजमहल में गंगा के पार एक बैराज बनाने की परिकल्पना की गई थी।इसके बाद भी, कई विशेषज्ञ इस समस्या में गए और उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। इस क्षेत्र में भारत और तत्कालीन पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को तय करते समय भारत के विभाजन के दौरान उद्गम जल की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गंगा के पार बैराज की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया था।

कलकत्ता बंदरगाह के संरक्षण के लिए परियोजना के निर्माण की मंजूरी 1960 में भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा दी गई थी।हालांकि, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को संभालने में इस मंत्रालय के अनुभव को देखते हुए, परियोजना का निष्पादन तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की जिम्मेदारी बन गया। बैराज के निर्माण का वास्तविक कार्य 1963-64 में शुरू हुआ था।

भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना

यह शुरू की गई सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक थी। इस बिंदु पर गंगा नदी का प्रवाह पूरे वर्ष भर रहता है। यहां तक कि नदी के मार्ग परिवर्तन के कार्य के समय भी प्रवाह 3000 घन मीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक के क्रम का था। निर्माण के मौसम का एक बड़ा हिस्सा कॉफर बांध के निर्माण के लिए खर्च किया जाना था जो कि निर्माण के लिए स्थायी कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक था।

बैराज

बैराज एक भूकंपीय क्षेत्र में महीन रेत पर स्थापित किया गया है। बैराज दो किमी लंबा है और इसमें 109 खंड हैं और इसे 76400 घन मीटर प्रति सेकंड से गुजरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैराज के घाट दो बड़ी रेलवे लाइनों और चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

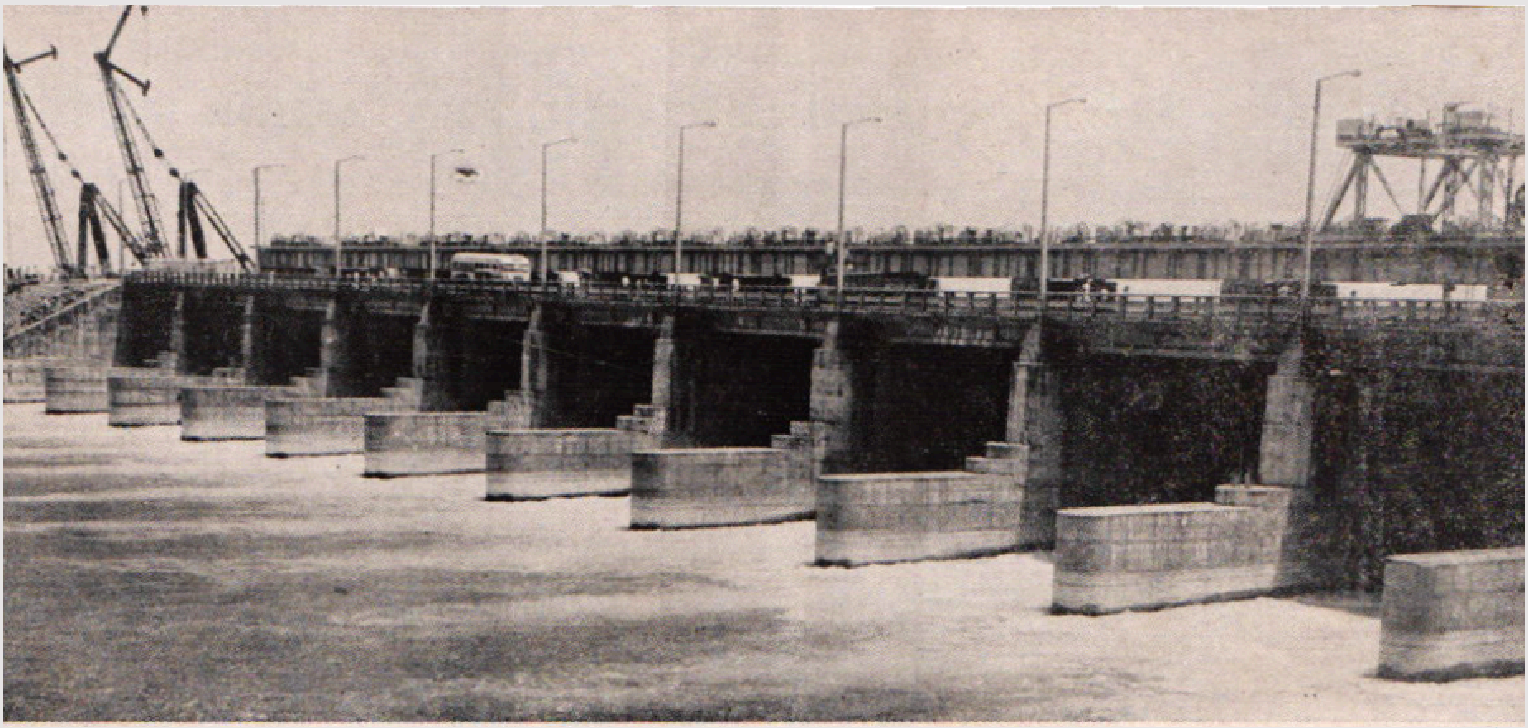

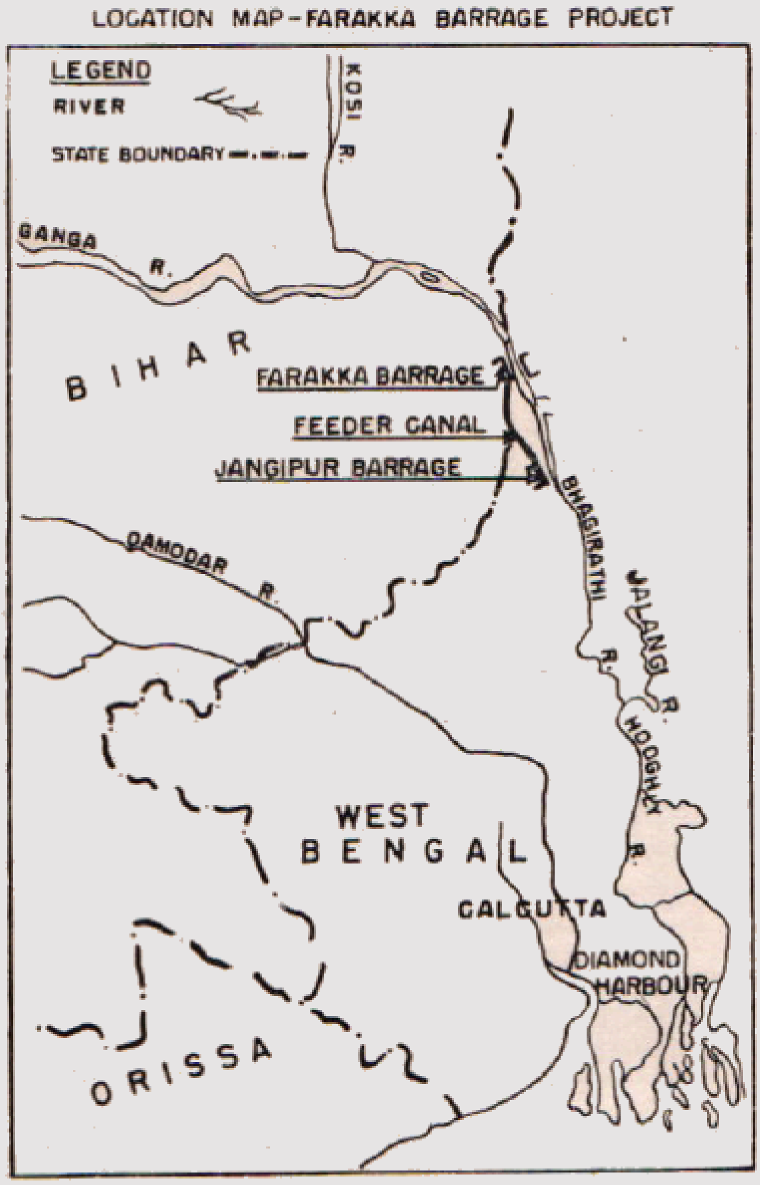

पोषक(फीडर)नहर – स्वेज से बड़ी

पोषक नहर, जो पानी को भागीरथी में ले जाती है, 38.3 किमी लंबी है और मानव निर्मित सबसे बड़ी नहरों में से एक है। इसकी तल चौड़ाई 151 मीटर है और पानी की गहराई 6 मीटर है। यह प्रसिद्ध स्वेज नहर से भी बड़ा है। परियोजना के अन्य कार्यों में जंगीपुर बैराज, नौवहन जलपाश और पोषक नहर पर पुल शामिल हैं।

भारतीय अभियांत्रिकी कौशल

विशाल बैराज के साथ-साथ अन्य संरचनाओं के निर्माण से संबंधित सभी तकनीकी समस्याओं को भारतीय इंजीनियरों द्वारा अद्वितीय निर्माण तकनीकों को अपनाते हुए सुलझाया गया।निर्माण की चरम अवधि के दौरान, विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियोजित हजारों मजदूरों के अलावा केवल विभाग द्वारा 4000 से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया गया था।

लाभ

इस परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ असंख्य हैं।पूरे वर्ष हुगली में पर्याप्त अपलैंड डिस्चार्ज प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के अलावा, इस परियोजना ने पहले ही देश के बाकी हिस्सों के साथ भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के बीच प्रत्यक्ष और सभी मौसम में संचार लिंक खोल दिया है। 1971 में बैराज के ऊपर एक लंबी-चौड़ी रेलवे लाइन खोली गई और 1972 में राष्ट्रीय राजमार्ग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया।इससे पहले, इस बिंदु पर, रेल के माल डिब्बों और सड़क परिवहन वाहनों दोनों को नदी के उस पार ले जाना पड़ता था जो श्रमसाध्य और समय लेने वाला था

नौसंचालन

पोषक नहर भागीरथी को गंगा से जोड़ने वाली अंतर्देशीय नौसंचालन की सुविधा भी प्रदान करती है जो कलकत्ता को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) तक जोड़ती है।

भारत-बांग्लादेश सहयोग

18 अप्रैल 1975 को ढाका में हुए भारत-बांग्लादेश समझौते के बाद पोषक नहर पहली बार 21 अप्रैल 1975 की सुबह बहनी शुरू हुई। यह समझौता फरक्का बैराज मुद्दे के लिए एक सफलता है और एक अंतरराष्ट्रीय नदी के विकास में दोनों पड़ोसी देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। परियोजना का संचालन शुरू होने से दोनों देशों के लाभ के लिए अंतिम सहमति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना संभव होगा।

फरक्का बैराज परियोजना (मुख्य विशेषताएं एक नज़र में)	
बैराज	
लंबाई	2244.4 मी. (7363.5 फीट)
खण्डों की संख्या	109
प्रत्येक खण्ड का विस्तार	18.3 मी. (60 फीट) निकास
डिजाइन निर्वहन	76400घनमी. (2.7मिलियन घन फीट) प्रति सेकंड
तालाब का स्तर	+ 21.9 मी. (+ 72 फीट)
उत्प्लाव का शिखर स्तर	+ 15.8 मी. (+52 फीट)
शीर्ष-नियामक	
तालाब का स्तर	+ 21.9 मी. (+72 फीट)
शीर्ष पर पूर्ण आपूर्ति स्तर	+21.6 मी. (+71 फीट)
डिजाइन निर्वहन	1135 घन मी. (40,000 घन फीट) प्रति सेकंड
स्वच्छ जलमार्ग	प्रत्येक 12.19 मीटर (40फीट) के 11खंड
शिखर स्तर	+ 18.1 मी. (+ 59.3 फीट)
पोषक नहर	
लंबाई	38.3 किमी. (23.8 मील)
डिजाइन निर्वहन	1135 घन मी.(40,000 घन फीट) प्रति सेकंड
तल की चौड़ाई	150.9 मी. (495 फीट)
पूर्ण प्रदाय गहराई	6.1 मी. (20 फीट)
जंगीपुर बैराज	
लंबाई	212.8 मी. (698 फीट)
खाड़ियों की संख्या	15
प्रत्येक खाड़ी का विस्तार	12.19 मी. (40 फीट)
शिखर स्तर	+ 12.8 मी. (+42 फीट)
लागत	रु.156.29 करोड़

(स्रोत: भागीरथ जुलाई 1975)

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी & ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in